April, 1994. The salient features of the PMRY are as under:

(i) All educated unemployed youth between the age of 18 and 35 belonging to families having total family income of less than Rs. 24,000/- per annum from all sources would be eligible for asistance under the scheme.

(ii) These educated unemployed entrepreneurs would be given a subsidy of 15% subject to a ceiling of Rs. 75,00/- each for starting the micro-enterprises.

(iii) They would be required to bring in 5% of the project cost as margin money.

(iv) Each entrepreneur will be eligible for a loan upto a ceiling or Rs. 1 lakh and this loan would not require a collateral guarantee.

(v) The entrepreneur selected under the scheme would be provided training, before the loan is disbursed.

(vi) Matric (passed or failed) student, ITI passed youth and all persons who have undergone Government sponsored technical courses for a minimum duration of 6 months will be eligible for assistance under the scheme.

(vii) Reputed Non-Governmental Organisation (NGOs) would also be associated in the implementation of the scheme.

(viii) A resevation of 22.5% for SC/ST and 27% for other backward classes (OBCs) has been provided.

(ix) The beneficiary should have been a permanent resident of the urban areas for 3 years.

Reserve Bank of India (RBI) have issued instructions to banks (excluding Regional Rural Banks) on September 28, 1993 for implementation of PMRY. The banks have also been advised to issued suitable instructions to all their Lead Bank Officers and the branches to effectively participated and implement the scheme.

भारतीय रिजर्व बैंक की आय और व्यय में अंतर

893. श्री राम जेठमलानी:
श्री वीरेन जे० शाह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक की आय और उसके द्वारा दिये जाने वाले व्यय के बीच का अंतर निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में आय और व्यय की राशि क्रमशः कितनी-कितनी थी और किया गया व्यय आय का कितने प्रतिशत था तथा आय का लाभांश कितने प्रतिशत थी;

(ग) क्या वर्ष 1980-81 की तुलना में वर्ष 1985-86 में यह प्रतिशत कम हो गया था;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में लाभांश और व्यय का प्रतिशत क्रमशः कितना-कितना था;

(ङ) वर्ष 1992-93 में लाभांश और व्यय का अलग-अलग प्रतिशत क्या था और उक्त अवधि के दौरान आय और व्यय की राशि क्रमशः कितनी-कितनी थी;

(च) क्या सरकार द्वारा आय की तुलना में व्यय में हुई असंगत वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों की समय-समय पर कोई समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार भविष्य में व्यय में कमी करने के लिये कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 1980-81 से 1992-93 तक की अवधि के दौरान व्यय की तुलना में कुल आय में निरंतर वृद्धि दिखाई दी है।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिये कुल आय, कुल व्यय, आय की तुलना में व्यय की प्रतिशता और आय की तुलना में अधिशेष की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नानुसार था:—

कुल आय.....	1009.53 करोड़ रुपये
कुल व्यय.....	349.53 करोड़ रुपये
आय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता	34.62
आय की तुलना में अधिशेष की प्रशितता	20.80

(ग) और (घ) 1985-86 के दौरान आय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता 56.20 और आय की तुलना में अधिशेष की प्रतिशतता 9.50 थी।

(ङ) वर्ष 1992-/93 के लिये, कुल आय, कुल व्यय, आय की तुलना में व्यय के प्रतिशतता और आय की तुलना में अधिशेष की प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नानुसार था:—

कुल आय.....	5632.12 करोड़ रुपये
कुल व्यय.....	4128.12 करोड़ रुपये
आय की तुलना में व्यय की प्रतिशतता	73.30
आय की तुलना में अधिशेष की प्रशितता	26.63

(च) जी, नहीं।

(छ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर ऋण

894. **श्री राम जेठमलानी:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1994 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "बैंक्स आस्कड टू गिव प्रायोरिटी टू स्माल सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राष्ट्रीकृत बैंकों को इस बात के निर्देश दिये हैं कि देश के 45 जिलों में लघु उद्योगों को उनकी आवश्कतानुसार ऋण प्रदान किये जाएं;

(ग) यदि हां, तो ये जिले किस-किस राज्य में स्थित है और प्रत्येक राज्य में कितने-कितने जिले हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन जिलों में स्थापित लघु इकाइयों के मालिकों को उन को प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी प्रदान क रने हेतु जन प्रचार माध्यम का उपयोग किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु और कुटीर उद्योगों की चल पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को भी आदेश जारी किये हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?